पश्चिम एशियाई देशों को प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों तथा खनिज जल का निर्यात

3345. **श्री हरीश रावत**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई देशों को प्रोसेस्ड और डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों तथा खनिज जल का निर्यात करने की सम्भावनाओं के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए पश्चिम एशियाई देशों को कोई अध्ययन दल भेजने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 1978 में साधित फलों तथा सब्जियों के निर्यात की संभाव्यताओं का एक अध्ययन किया गया था । व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा 1981 में सऊदी अरब तथा कुवैत को साधित फलों तथा सब्जियों के लिए एक सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम प्रायोजित किया गया ।

(ख) पैकेजिंक तथा क्वालिटी सुधारने, समुचित नौवहन सुविधाएं प्रदान करने तथा इन देशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

Balance of Payment

3346. PROF RUPCHAND PAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the balance of payment position is in a precarious state;

(b) if so, whether the liberalised import is the main reason for this pitiable condition;

(c) if so, whether the Government have decided to change the liberalised import polity; and

(d) if not, the reasons for the same?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) In the past few years, the balance of payments situation has been a matter of concern; however, the position is not precarious Government has adopted a multi-pronged strategy for tackling this problem, and considerable success has been achieved in implementing this strategy.

Details regarding development in the balance of payments can be seen in Economic Survey 1982-83.

(b) to (d) The deterioration in foreign exchange reserves arose principally from the massive increase in oil prices since 1979 which pushed up the oil bill from Rs. 1687 crores in 1978-79 to Rs. 5587 crores in 1980-81. Prices of other imports had also risen sharply during that period. This had happened at a time when exports faced severe external constraints arising from sluggish demand in world markets and increasing protectionist tendencies.

There has been no liberalisation of imports as such. Import Policy has sought to combine the objective of reducing the growth of import with the need to continue the liberal access to raw materials and capital goods for priority sector. Tariff policies are being effectively used to provide further protection to indigenous industries whenever appropriate.